यूपीसीडा बना रहा 20 हजार एकड़ का भूमि बैंक

- 47वीं बोर्ड बैठक में अलग अलग प्रस्तावों पर लगी मुहर

जासं, कानपुर : उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) प्रदेश में निवेशकों के लिए 20 हजार एकड़ से अधिक भूमि बैंक तैयार कर रहा है। इसके अंतर्गत निवेशकों को प्रदेश की बंद इकाइयों की भूमि दी जाएगी। इससे वे अपने उद्योगों को लगाकर प्रदेश का विकास कर सकेंगे। यह बात लखनपुर स्थित यूपीसीडा मुख्यालय में 47वीं बोर्ड बैठक में संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयूर माहेश्वरी ने कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मुख्य सचिव व अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग व लाजिस्टिक नीति के तहत छह उद्यमियों को यूनिक आइडी पत्र वितरित किए। बोर्ड बैठक में भूमि बैंक, आवासीय नीति से जुड़े प्रस्तावों को पारित किया गया।

बोर्ड बैठक में भूमि बैंक के संबंध में एटा के ग्राम ओरनी में 78.46 एकड़ की अधिगृहीत भूमि का तलपट मानचित्र स्वीकृत किया गया। प्राधिकरण की पुनर्क्रय नीति के तहत उत्तर प्रदेश ड्रग्स फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड जो उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम है, उसकी बंद इकाई की 12.84 एकड़ भूमि फिर से खरीदने की स्वीकृति दी गई। बाराबंकी में 69.86 एकड़ भूमि के आवंटन के लिए बल्क आवंटन नीति स्वीकृत की गई। यूपीसीडा द्वारा नगर निगम, नगर पालिका से हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्र में विकास कराने के लिए कन्सल्टेंट का चयन किया गया। मुख्य सचिव ने बरेली के पंचमुखी हनुमान इंटरप्राइजेज, लखनऊ के आरएस विजन इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड समेत छह कंपनियों के अफसरों को यूनिक आइडी दी गई।